

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 57/2024

उनवान

तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थी

बनाम

मायाकुंवर पत्नि महेन्द्रसिंह राजपुत निवासी वखतपुरा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 21.8.2024

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का मादलदा के मौजा वखतपुरा की खाता संख्या 152 (नया) 132 (पुराना) के सर्वे नम्बर 2434/2430 रकबा 0.36 हे० किस्म-का.का. भूमि खातेदार मायाकुंवर पत्नि महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी वखतपुरा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीया द्वारा ग्रामीण सड़क से 60 फीट की दूरी पर रकबा 0.08 हे० भूमि में टिनशेड का निर्माण किया जाकर मशीनरी स्थापित कर राईसु मिल का संचालन किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा उक्त कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर भूमि आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की जाकर उक्त सर्वे नम्बर 2434/2430 रकबा 0.36 हे० में से रकबा 0.08 हे० भूमि पर गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। अतः प्रार्थीया के नाम दर्ज पटवार हल्का मादलदा के मौजा वखतपुरा के खाता संख्या 152 (नया) 132 (पुराना) के सर्वे नम्बर 2434/2430 रकबा 0.36 हे० किस्म-का.का. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमों की पालना नहीं की जाने से सद्भावी कृषक की श्रेणी में नहीं आने से उक्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित कराने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीया की ओर से श्री पवन लुहार, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया के नाम दर्ज खातेदारी भूमि आवंटित नहीं होकर पैतृक कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीया द्वारा फुड प्रोसेसींग युनिट स्थापित की जाकर कृषि भूमि को उन्नत बनाने की मशीन लगी हुई है। राजस्थान सरकार के NOTIFICATION No- F.6(26)Revenue-6/14/70 Jaipur, Dated: 09-09-2020 के रूल 6ए. में स्पष्ट लिखा है कि खातेदार अपनी कृषि भूमि का उपयोग फुड प्रोसेसींग युनिट के लिए करेगा जो 10 हे० से ज्यादा नहीं होगा। अप्रार्थीया की कृषि भूमि में लगी उक्त युनिट कृषि उत्पादन की प्रोसेसींग करने की युनिट है कोई उत्पाद बनाने का उद्योग नहीं है। अप्रार्थीया द्वारा भूमि का अन्य उपयोग नहीं किया है, न ही गैर कृषि कार्य किया है। अप्रार्थीया ने उक्त युनिट के लिए ऋण लिया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान कृषि भूमि पर निर्मित होने पर ही देय है। अप्रार्थीया द्वारा किसर शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है जिस कारण उसकी भूमि को सिवायचक घोषित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही राज्य सरकार के नोटीफिकेशन एवं कृषि उत्पादों को उन्नत कर कृषक को समृद्ध बनाने के प्रयासों के विरुद्ध होकर राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना होना बताया। तत्पश्चात् प्रकरण में अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, राजस्व अभिलेख तथा अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ 6(26)राजस्व-6/14/70 दिनांक 09.9.2020 का अवलोकन करने पर ज्ञात आया कि कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से ली जाने वाली उपज को उन्नत बनाने के लिए बिना भूमि संपरिवर्तन करीये फुड प्रोसेसींग युनिट स्थापित कर सकता है। इस प्रकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.9.2020 में वर्णित निर्देशों के तहत प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पोषणिय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2024 को जारी किया गया।



(अन्जु शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी